पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राजीव कुमार उर्फ राजीव कुमार

बनाम

आरती कुमारी

2018 की विविध अपील सं. 352

27 सितंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

विचार के लिए मुद्दा

क्या पारिवारिक न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) और 13(1)(i-b) के तहत दायर तलाक याचिका को बिना नोटिस जारी किए, मुद्दे तय किए बिना, या परीक्षण किए बिना, तथा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 9 के तहत पुनर्मिलन का प्रयास किए बिना, अस्वीकृत करने में उचित था?

हेडनोट्स

परिवार कानून – तलाक – बिना परीक्षण के याचिका का खारिज होना – पुनर्मुखी आदेश – प्रक्रिया – परिवार अदालत अधिनियम, 1984 – धाराएं 9 और 10 – पुनर्मिलन का प्रयास करने की जिम्मेदारी – परिवार अदालत द्वारा अनुपालन न करना न्यायिक अनुशासन – तर्कसंगत आदेशों की आवश्यकता – यांत्रिक और सतही खारिज करने की आलोचना – पुनर्मुखी – डे नोवो सुनवाई का आदेश – प्रक्रियात्मक सुरक्षा के अनुपालन पर जोर – न्यायिक प्रशासन – परिवार अदालत के न्यायाधीशों की संवेदनशीलता – निर्णय का प्रसार आदेशित.

निर्णय: उच्च न्यायालय ने देखा कि परिवार न्यायालय ने परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 9 के तहत पक्षों के बीच सुलह के लिए प्रयास करने के वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया। विवाद को सुलझाने या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया, जिसने परिवार न्यायालय अधिनियम के उद्देश्य को कमजोर कर दिया। विवादास्पद आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को परिवार न्यायालय के पास फिर से भेजा गया, विशिष्ट निर्देशों के साथ कि दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया जाए, सबूत और सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए, और परिवार न्यायालय अधिनियम के अनुरूप छह महीनों के भीतर एक नया, तर्कसंगत निर्णय पारित किया जाए।

न्याय दृष्टान्त

के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपाः (2013) 5 एससीसी 226; जलेंद्र पदियारी बनाम प्रगति छोटराय: **(2018) 16** एससीसी **773**

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1989

मुख्य शब्दों की सूची

*****

प्रकरण से उत्पन्न

तारीख 12.03.2018 को पारित आदेश से, जो तलाक मामले संख्या 38 वर्ष 2017 में परिवार न्यायालय, बेगूसराय द्वारा दिया गया है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राय मुकेश शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : कोई नहीं

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: रवि राज, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील सं. 352

==========

राजीव कुमार उर्फ राजीव कुमार, पिता- डॉ. शंकर प्रसाद सुमन, निवासी ग्राम- सती चौरा, थाना- बलिया, जिला- बेगूसराय।

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

आरती कुमारी, पति- राजीव कुमार उर्फ राजीव कुमार, निवासी ग्राम- सती चौरा, थाना- बलिया, जिला- बेगूसराय। वर्तमान में आरती कुमारी, पिता- स्वर्गीय सुरेंद्र साह, निवासी ग्राम- सकसोहरा, थाना- बाढ़, जिला-पटना।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राय मुकेश शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : कोई नहीं

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे

सी.ए.वी. निर्णय

प्रति : माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

दिनांक : 27-09-2024

वर्तमान अपील प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगुसराय द्वारा 2017 का तलाक मामला सं. 38 में दिनांक 12.03.2018 को पारित आदेश के खिलाफ है, जिसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(1-क)(1-ख) के तहत तलाक की प्रार्थना को विचारणीय नहीं माना गया और खारिज कर दिया गया है।

2. वर्तमान अपील के संक्षिप्त रूप से बताए गए तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता का विवाह दिनांक 05.05.2013 को उत्तरदाता के साथ संपन्न किया गया था। इसके बाद,

उत्तरदाता अपने वैवाहिक घर में अपीलकर्ता के साथ आई जहाँ उत्तरदाता पाँच दिनों तक अच्छी तरह से रही। इसके बाद, उत्तरदाता के भाई और अन्य रिश्तेदार उसे माता-पिता के घर ले गए। यह दावा किया जाता है कि उसके माता-पिता के घर जाते समय, उत्तरदाता महंगे सामान, गहने और कपड़े ले गई। तलाक याचिका में यह कहा गया है कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उसके घर गया था, लेकिन उत्तरदाता ने किसी न किसी बहाने से वैवाहिक घर में शामिल नहीं होने का बहाना बनाया है। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता को वापस लाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की लेकिन अंत में उत्तरदाता ने अपीलकर्ता को जवाब दिया कि उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह किया और दोनों परिवारों के बीच कोई मेल नहीं था। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता/पत्नी को पति और पत्नी के रूप में वैवाहिक जीवन जीने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन उत्तरदाता वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थी। यह दावा किया जाता है कि जब भी अपीलकर्ता उत्तरदाता/पत्नी को वापस लाने के लिए जाता था, तो उसकी माँ उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी और इस बात की निंदा करती थी कि अपीलकर्ता का घर गाँव में है, वह बेरोजगार है और अपने माता-पिता पर निर्भर है और अपीलकर्ता के पास आर्थिक रूप से उत्तरदाता को संतुष्ट करने की कोई क्षमता नहीं है। उत्तरदाता द्वारा यह बताया गया कि उसका जीवन स्तर उच्च है और वह अपना जीवन नहीं जी सकती क्योंकि अपीलकर्ता 2500-3000 रु/- प्रति माह कमाता है और उक्त कमाई उत्तरदाता का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तरदाता की इच्छा है कि अपीलकर्ता को अपना घर और माता-पिता को छोड़ देना चाहिए और उत्तरदाता के पिता के घर पर रहना चाहिए जिसका अपीलकर्ता ने पूरी तरह से विरोध किया था। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता को शांत करने की कोशिश की लेकिन वह उक्त मामले पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं थी। जब उत्तरदाता शादी के पाँच दिनों के बाद अपने पिता के घर गई, तो अपीलकर्ता उत्तरदाता के पिता के घर गया, लेकिन उत्तरदाता ने शारीरिक संतुष्टि से इनकार कर दिया, जिससे

अपीलकर्ता को अपनी पत्नी/उत्तरदाता के साथ वैवाहिक जीवन जीने से वंचित किया जा रहा था। तलाक याचिका में यह कहा गया है कि दिनांक 10.05.2014 को, अपीलकर्ता अपने पिता और शुभचिंतक के साथ उत्तरदाता के घर गया और समाज के सभी प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवियों के साथ पंचायती आयोजित की गई, लेकिन उत्तरदाता के साथ-साथ उसकी माँ और उसका भाई पंचायत के फैसले का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलकर्ता, उसके पिता और रिश्तेदारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद अपीलकर्ता अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ वापस लौट आई। दिनांक 23.05.2014 को, उत्तरदाता/पत्नी को पंजीकृत डाक के माध्यम से कानूनी सूचना भेजा गया है, लेकिन उत्तरदाता ने न तो कानूनी सूचना का जवाब दिया और न ही वह आज तक वैवाहिक घर आई है। उत्तरदाता को सूचना देने के बाद भी, अपीलकर्ता उत्तरदाता के पिता के घर गया और अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अपीलकर्ता को संबंध तोड़ने की धमकी दी गई है अन्यथा अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को गलत तरीके से फंसाया जाएगा और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवाह के पाँच दिनों के लिए, अपीलकर्ता ने वैवाहिक जीवन नहीं बिताया क्योंकि उत्तरदाता अपने पिता के घर पर लगातार रह रही है। यह दावा किया गया है कि अंत में दिनांक 11.05.2013 को, उत्तरदाता अपीलकर्ता को छोड़कर, हर समय के लिए अपने पिता के घर चली गई और अब अपीलकर्ता अकेला रह गया है और उसे वैवाहिक जीवन से वंचित किया जा रहा है और अपीलकर्ता को उत्तरदाता के क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा। अंत में, अपीलकर्ता को संदेह है कि उत्तरदाता का चरित्र खराब है और दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता का वैवाहिक जीवन इतने वर्षों तक पूरा नहीं हुआ है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में न तो विरोधी पक्ष/उत्तरदाता को सूचना जारी किया गया है और न ही कोई मुद्दा तैयार किया

गया है और अपीलकर्ता या विरोधी पक्ष की ओर से गवाहों से पूछताछ किए बिना, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगुसराय ने वैवाहिक मुकदमा को खारिज कर दिया क्योंकि यह रखरखाव योग्य नहीं है।

4. वर्तमान मामले में, योग्यता के आधार पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामले का निर्णय मामले की योग्यता के आधार पर नहीं किया गया है। नियमित और अनौपचारिक तरीके से, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना वैवाहिक मुकदमे को खारिज कर दिया है। प्रथम आदेश पत्र दिनांक 11.05.2017 से अंतिम आदेश पत्र दिनांक 12.03.2018 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जिस तरीके से न्यायालय ने उक्त मामले में कार्यवाही की है और न्यायालय द्वारा परिवार न्यायालय की आत्मा का पालन नहीं किया गया है। प्रथम आदेश पत्र दिनांक 11.05.2017 सिरिस्तेदार रिपोर्ट के बारे में बताता है। 26.05.2017 को सिरिस्तेदार ने 12.06.2017 को हुई मामले की सुनवाई और पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आवेदक की ओर से 12.06.2017 उपस्थिति दर्ज की गई है, मामला बुलाया गया है और आवेदक के अनुरोध पर मामले को सुनवाई के लिए दिनांक 17.07.2017 के लिए तय किया गया था। दिनांक 17.07.2017 को आवेदक की उपस्थिति दर्ज की गई और संशोधन याचिका दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया। दिनांक 21.08.2017 को आवेदक की उपस्थिति और हलफनामे के साथ संशोधन के लिए याचिका दायर की गई और अभिलेख को 13.09.2017 पर रखने का आदेश दिया गया। 13.09.2017 को आवेदक की ओर से उपस्थिति दर्ज की गई थी और उसी तारीख को पीठासीन अधिकारी वर्तमान ड्यूटी पर थे और अभिलेख को दिनांक 18.11.2017 को पेश करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 18.11.2017 को आवेदक की ओर से समय याचिका दायर करने के साथ-साथ विरोधी पक्ष की उपस्थिति भी दर्ज की गई और उसी तारीख को पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे और अभिलेख दिनांक

10.01.2018 को पेश करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 10.01.2018 को, आवेदक की ओर से उपस्थिति दर्ज की गई थी और 1,000 रु/- यात्रा करने और रहने के लिए उत्तरदाता को दिया गया था और प्रवेश के साथ-साथ संशोधन याचिका पर सुनवाई के लिए दिनांक 27.01.2018 तय किया गया था। दिनांक 27.01.2018 को, आवेदक की ओर से उपस्थिति दर्ज की गई थी और उसी तारीख को पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे और अभिलेख दिनांक 01.02.2018 को पेश करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 01.02.2018 को, आवेदक की उपस्थिति दर्ज की गई थी और उसी तारीख को पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे और अभिलेख दिनांक 09.02.2018 को पेश करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 09.02.2018 को, आवेदक की उपस्थिति दर्ज की गई थी और उसी तारीख को पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे और अभिलेख दिनांक 12.03.2018 को पेश करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 12.03.2018 को, आदेश नियमित तरीके से पारित किया गया है क्योंकि पीठासीन अधिकारी दिनांक 18.11.2017, 27.01.2018, 01.02.2018 और 09.02.2018 को लगातार छुट्टी पर थे और अचानक 12.03.2018 पर पीठासीन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिका विचारणीय नहीं थी और उसे खारिज कर दिया गया था।

5. दिनांक 12.03.2018 को, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगुसराय ने आकस्मिक और नियमित तरीके से आदेश पारित किया है और यह निम्नानुसार हैः

> *"आवेदक का हाजिरी दिया गया। पुकार पर संदेह उपस्थित है। आवेदक का कथन है की आरती कुमारी के साथ दिनांक 06-05-2023 को शादी हुई थी। घर में हमेशा झगड़ा करती थी। संदेह है कि किसी के साथ नाजायज सम्बन्ध भी है।*
>
> *सूना। अवलोकन किया। वाद लगने का आधार पोषणीय नहीं है। अतः मुकदमा ख़ारिज किया जाता है।"*

6. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता और उत्तरदाता ने दिनांक 05.05.2013 को

विवाह किया और पति/अपीलकर्ता को अपनी पत्नी/उत्तरदाता के साथ वैवाहिक कलह का सामना करना पड़ा और अपीलकर्ता ने राहत पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पारिवारिक न्यायालय ने विवादग्रस्त पक्षों को सुने बिना अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि दोनों पक्ष वर्तमान मामले में पेश हुए और संबंधित न्यायालय ने पक्षों के विवाद के सुलह के लिए कोई प्रयास नहीं किया है जो परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 9 की आत्मा है जिसे यहाँ नीचे के रूप में प्रस्तुत किया गया है:-

> ***9. निपटान के लिए परिवार न्यायालय का प्रयास करने का कर्तव्य है-*** *(1) हर एक वाद या कार्यवाही में, परिवार न्यायालय द्वारा पहली बार में प्रयास किया जाएगा, जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुरूप ऐसा करना संभव है, वाद या कार्यवाही के विषय-वस्तु के संबंध में पक्षों की समझौते पर पहुंचने में सहायता करने और उन्हें राजी करने के लिए और इस उद्देश्य के लिए एक परिवार न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, ऐसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है जैसा वह उचित समझे।*
>
> *(2) यदि, किसी भी वाद या कार्यवाही में, किसी भी स्तर पर, परिवार न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच समझौते की उचित संभावना है, तो परिवार न्यायालय कार्यवाही को उस अवधि के लिए स्थगित कर सकता है जो वह उचित समझे ताकि ऐसा समझौता करने के लिए प्रयास किए जा सकें।*
>
> *(3) उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति, कार्यवाहियों को स्थगित करने की, न कि उसके अवमूल्यन में, परिवार न्यायालय की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त होगी।*

7. ***के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा, (2013) 5 एस.सी.सी. 226*** में संदर्भित, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनु. 39 पर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> *"39. अक्सर, वैवाहिक विवाद में गलतफहमी का*

कारण तुच्छ होता है और इसे सुलझाया जा सकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान की एक विधि के रूप में मध्यस्थता को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। हमने कई वैवाहिक विवादों को मध्यस्थता केंद्र को भेजा है। हमारे अनुभव से पता चलता है कि लगभग 10 से 15 प्रतिशत वैवाहिक विवाद इस न्यायालय में विभिन्न मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से निपटाए जाते हैं। इसलिए, हम महसूस करते हैं कि शुरुआती चरण में यानी जब विवाद को परिवार न्यायालय या पहली बार सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा लिया जाता है, तो इसे मध्यस्थता केंद्रों को भेजा जाना चाहिए। वैवाहिक विवाद, विशेष रूप से वे जो बच्चे की अभिरक्षा, रखरखाव आदि से संबंधित हैं, मध्यस्थता के लिए पहले से ही उपयुक्त हैं। परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 9 परिवार न्यायालय को वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए प्रयास करने का आदेश देती है और इन प्रयासों में परिवार न्यायालयों को परामर्शदाताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यदि परामर्शदाता अपने प्रयासों में विफल भी हो जाते हैं, तो भी परिवार न्यायालयों को पक्षकारों को मध्यस्थता केंद्रों में निर्देशित करना चाहिए, जहां पक्षकारों के बीच मध्यस्थता करने के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं। मध्यस्थता के कौशल में प्रशिक्षित होने के कारण, वे अच्छे परिणाम देते हैं।

8. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय विचारण स्तर पर सबसे अनुभवी न्यायालयों में से एक है और परिवार न्यायालय को मुख्य रूप से सुलह या मध्यस्थता के माध्यम से या अन्य तरीकों से वैवाहिक विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए विशेष कार्य सौंपा गया है जो पक्षों के लिए उपयुक्त है, लेकिन संबंधित परिवार न्यायालय द्वारा उसी सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित न्यायालय ने वैधानिक प्रावधान के अनुसार आवश्यक मूल सिद्धांत का पालन किए बिना बहुत ही अनौपचारिक तरीके से वैवाहिक विवाद को संभाला है। विवाह के रद्द होने या तलाक की कार्यवाही से संबंधित वैवाहिक विवाद से संबंधित मामला एक गंभीर मामला है और यह पति और पत्नी के पूरे जीवन को जोड़ता है जिनके खिलाफ निरर्थकता या तलाक की घोषणा के लिए एक

डिक्री मांगी गई है। उक्त मामले में, न्यायालय को आदेश पारित करते समय यांत्रिक दृष्टिकोण का पालन नहीं करना चाहिए।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***जालेंद्र पाढियारी बनाम प्रगति छोटरे, (2018) 16 एस.सी.सी. 773*** में रिपोर्ट की गई मामले की अनु. **16** पर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है**:**

> *"16. बार-बार, इस न्यायालय ने न्यायालयों पर प्रत्येक मामले में तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें वाद के पक्षकारों के मामले के अनावृत तथ्यों का वर्णन, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षों द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतिकरण, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और मामले में उत्पन्न होने वाले सभी भौतिक मुद्दों पर साक्ष्य की सराहना के आधार पर दर्ज किए गए निष्कर्षों के समर्थन में कारण शामिल होने चाहिए।"*

10. दिनांक 05.09.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

> *प्रथम दृष्टया में, आक्षेपित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है और तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिप्रेषण का मामला है क्योकि भौतिक जानकारी पर कोई विचार नहीं किया गया है।*
>
> *2. उत्तरदाता को एक अवसर देने के लिए, इस मामला को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें। यदि उत्तरदाता की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो मामले का निर्णय उपलब्ध अभिलेखों के साथ किया जाएगा।*
>
> *3. इस मामले को दिनांक 19.09.2024 पर फिर से सूचीबद्ध करें।*

11. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, यह स्पष्ट है कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगुसराय ने बिना किसी समझदारी के और नियमित और आकस्मिक तरीके से आदेश पारित किया है, संबंधित न्यायालय ने संवेदनशील मामले को संभाला है जो वैवाहिक विवाद से संबंधित है और इस तरह के आदेश को दरकिनार किया जाना

चाहिए। तदनुसार, परिवार न्यायालय, बेगुसराय के प्रधान न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा 2017 के तलाक मामला सं. 38 में पारित दिनांक 12.03.2018 के आदेश को रद्द कर दिया गया है। दोनों पक्षों को सूचना देने के साथ-साथ दोनों पक्षों को अपनी दलीलें दायर करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के बाद मामले की नए सिरे से सुनवाई करने के लिए मामला परिवार न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है और उसके बाद, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मुद्दों का फैसला किया जाता है और इस फैसले की प्रति प्राप्त करने/पेश करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाता है।

12. पारिवारिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को संवेदनशील बनाना आवश्यक है क्योंकि वर्तमान मामले को निर्णय में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पारिवारिक न्यायालय ने उक्त मामले को किस प्रकार लापरवाही और नियमित तरीके से निपटाया है और किस प्रकार पारिवारिक न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की आत्मा के विरुद्ध कार्य किया है। उक्त पहलू पर, महापंजीयक से अनुरोध है कि वे इस निर्णय की एक प्रति पारिवारिक न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारियों के बीच प्रसारित करें और आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी को एक प्रति भेजें।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

आलोक/शहज़ाद-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।